viuh ckr

तिब्बत में चीन सरकार की क्रूरता निंदनीय

चीन सरकार द्वारा तिब्बत में किए जा रहे दमन का प्रभावी विरोध यथाशीघ्र जरूरी है। तिब्बत पर चीन के अवैध नियंत्रण से उपजा संकट एक विश्वस्तरीय संकट है। तिब्बत में चीन सरकार के हिंसक व्यवहार से चीन के सामान्य व्यक्ति भी विश्व के अन्य देशों की नजर में अमानवीय तथा क्रूर समझे जाने लगे हैं। इस प्रकार इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल करना होगा।

अभी जुलाई माह में तिब्बत के तावू जिले में तिब्बतियों पर चीन की सेना द्वारा हिंसक हमला किया गया। वे तिब्बती भिक्षु–भिक्षुणी तथा आमजन परमपावन दलाई लामा जी का जन्म दिन मना रहे थे। दलाई लामा को चीन की सरकार अपना शत्रु समझती है। वह उनके समर्थकों–प्रशंसकों को तिब्बत पर अपने अवैध आधिपत्य के खिलाफ खतरा समझती है। इसीलिए उनने तावू जिले में 6 जुलाई 2013 को दलाई लामा के जन्मोत्सव में हिंसापूर्ण सैनिक कार्यवाही की। चीन के इस व्यवहार की चौतरफा आलोचना हर तरह से जायज है।

तिब्बत में चीन सरकार के क्रूर आचरण का ही परिणाम है कि अनेक तिब्बती आत्मदाह कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ही लगभग डेढ़ सौ तिब्बती अपने ही शरीर में आग लगाकर तिब्बत की आजादी के लिए बलिदान कर चुके हैं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण तथा विचलित कर देने वाली आत्मदाह की घटनायें तिब्बत के बाहर भी हो रही हैं। निर्वासित तिब्बती भी यही चाहते हैं कि तिब्बत आजाद हो, चीन सरकार द्वारा तिब्बतियों पर दमन बंद करने के लिए विश्व समुदाय कदम उठाए तथा दलाई लामा ससम्मान तिब्बत लाए जायें। इन्हीं मांगों को लेकर इसी वर्ष दो निर्वासित तिब्बती सिर्फ नेपाल में ही आत्मदाह कर चुके हैं। भारत में भी ऐसा पहले हो चुका हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार द्वारा आत्मदाह नहीं करने हेतु बार–बार तिब्बतियों से आग्रह करने के बावजूद आत्मदाह का सिलसिला रूक नहीं रहा है।

तिब्बत की राजधानी ल्हासा में थंका पेंटिंग से जुड़ा एक भव्य धार्मिक उत्सव होता है। इस बार इस समारोह की चीनी सैनिकों ने घेराबंदी कर दी। सैनिकों के घेरे में धार्मिक समारोह की बात विचित्र भले लगे, किन्तु सत्य है। इससे भी प्रमाणित होता है कि तिब्बत में स्थिति बहुत ही गंभीर है। विश्व समुदाय को चाहिये कि वह चीन सरकार पर उपयुक्त दबाव बढ़ाये ताकि तिब्बत में जारी तिब्बतियों पर अत्याचार बंद हो।

चीन सरकार की फिलहाल भारी भरकम राशि खर्च करके एक अफवाह फैलाने में लगी है। इसे मल्टी मिलियन डॉलर प्रोपगेंडा कहना बेहतर होगा। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सातवीं शताब्दी में तिब्बती सम्राट सोगसन मतेन गांबो की दो पत्नियाँ थीं। पहली पत्नी नेपाल की थी और दूसरी पत्नी चीन की। उसी दूसरी पत्नी को आधार बनाकर चीन की सरकार प्रचारित करने लगी है कि तिब्बत तो चीन का ही है। इस प्रकार चीन की सरकार ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करने तथा अपनी सुविधा के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने में लगी है। विश्व समुदाय को तिब्बत के संबंध में गुमराह रखने हेतु चीन सरकार का यह नया, हास्यास्पद और खतरनाक हथकंडा है।

चीन सरकार तिब्बत पर अपने अनुचित नियंत्रण को उचित ठहराने के लिए प्रारम्भ से ही अनेक उचित–अनुचित तरीके अपनाती आ रही है। इसके बावजूद सच्चाई छिपाए नहीं छिपती। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिब्बत के विषय में चीन की सरकार बेनकाब हो चुकी है। अमेरिका के मानवाधिकार एवं श्रम विभाग के सहायक सचिव ने हाल ही तिब्बत की स्थिति को काफी चिंताजनक बताया है। उनका मत है कि तिब्बत की वास्तविकता को समझने के लिए वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जाए तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ अपना प्रतिनिधिमंडल भेजे। वे वास्तविकता को देखें–समझें और चीन सरकार से मिलें। तिब्बत के हालात में सुधार हेतु चीन सरकार पर दबाव डालें।

वास्तव में चीन सरकार की साम्राज्यवादी हठधर्मिता का जवाब देना ही होगा। जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है, भारत की एकता–अखंडता और सुरक्षा खतरे में है। वह 1962 में हजारों वर्ग मील भारतीय भूभाग पर अवैध कब्जा कर चुका है। अभी भी वह भारत के कई इलाकों को चीन का इलाका बता रहा है। इसी 13 अगस्त 2013 को अरूणाचल प्रदेश के चांगलागम क्षेत्र में चीन के सैनिक बीस किलोमीटर अंदर तक घुस आए। दो दिन यहीं डटे रहे। समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव तथा भारतीय जनता पार्टी सांसद जेपी नड्डा ने चीन के इस उपनिवेशवादी भारत विरोधी कदम की तीखे शब्दों में आलोचना की है। भारत के सभी राजनेताओं को चाहिए कि इस मामले में चीन के प्रति कड़ा रूख अपनायें। इसी साल अप्रैल माह में चीन ने लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ की थी।

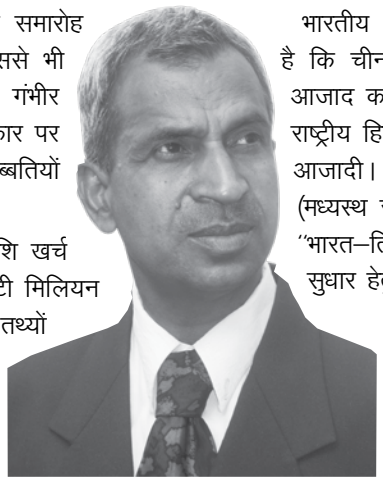

भारतीय संसद का 14 नवम्बर 1962 का सर्वसम्मत संकल्प है कि चीन के अवैध कब्जे से भारतीय भूभाग को पूरी तरह आजाद कराया जाएगा। इस प्रस्ताव पर अमल करना भारत के राष्ट्रीय हित में है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है तिब्बत की आजादी। फिर से भारत और चीन के बीच तिब्बत का बफर स्टेट (मध्यस्थ राज्य) होना। फिर से ''भारत–चीन सीमा'' की जगह ''भारत–तिब्बत सीमा'' का होना। अतः तिब्बत की स्थिति में सुधार हेतु सर्वप्रमुख भूमिका भारत को ही निभानी होगी। ◆

प्रो० श्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)
E-mail :- shyamnathji@gmail.com

सिक्योंग ने भारत को 67 वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी

(तिब्बत डॉट नेट, धर्मशाला, 15 अगस्त)

तिब्बती जनता के राजनीतिक नेता सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे ने गुरुवार 15 अगस्त को भारत के 67वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतवासियों को बधाई दी है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा धर्मशाला में आयोजित एक समारोह में देशवासियों को बधाई देते हुए डॉ. सांगे ने कहा, " भारत सरकार और भारत की जनता ने तिब्बती जनता और हमारे आध्यात्मिक तथा सबसे सम्मानित नेता परमपावन दलाई लामा के प्रति जो आतिथ्य और दयालुता दिखाई है उसके लिए हम एक बार फिर के प्रति इस बात के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं एक तिब्बती स्कूल में पढ़ा हूं जहां हम हर साल जन–गण–मन गाते थे और भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराते थे और इसमें हमें गर्व की अनुभूति होती थी। भारत देश और यहां की जनता ने उदारता से हमारी मेजबानी की है और हम तिब्बती भारत में कानून का पालन करने वाले निवासी रहे हैं। हम एक बार फिर यह कहना चाहते हैं, धन्यवाद भारत।" सिक्योंग ने कहा, "भारत दुनिया भर के लिए एक चमकता हुआ उदाहरण है। यह न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि सही मायने में विविधता में एकता का प्रतिनिधि है, जिसका तिब्बती अनुसरण करते हैं और उसे एक अच्छे रोल मॉडल की तरह स्वीकार करते हैं।

बाद में स्थानीय भारतीय प्रशासन द्वारा आयोजित समारोह में स्वास्थ्य के कलोन (मंत्री) डॉ. सेरिंग वांगचुक, सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबध के सचिव श्री टाशी फुंत्सोक और तिब्बती बस्ती अधिकारी श्री सोनम दोरजी शामिल हुए। इस समारोह में तिब्बती इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के कलाकारों ने लॉयन डांस किया। ◆

तिब्बत की दु:खद घटनाएं चीन के लिए शर्म की बात है: दक्षिण अफ्रीका के सांसद

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 2 अगस्त)

तिब्बतियों की शिकायतों के समाधान करने की जगह 120 से ज्यादा तिब्बतियों को आत्मदाह के लिए मजबूर करके चीन सरकार ने अपनी अंतरराष्ट्रीय गरिमा और विश्वसनीयता खो दी है। दक्षिण अफ्रीका के एक सांसद ने 29 जुलाई को यह बात कही। अफ्रीका के इनकाथा फ्रीडम पार्टी के सांसद डॉ. मारियो ओरियानी–एम्ब्रोसिनी ने कहा कि सच तो यह है कि तिब्बत में हो रही दु:खद घटनाओं पर चीन सरकार की बेरुखी अब नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध तक बढ़ चुकी है।

फिलहाल कैंसर का इलाज करा रहे डॉ. ओरियानी एम्ब्रॉसिनी ने कहा कि तिब्बत में होने वाली दु:खद घटनाओं के प्रति वह अपना गुस्सा इसलिए जाहिर कर रहे हैं क्योकि अब दक्षिण अफ्रीका या कहीं और के बारे में कुछ कहने के लिए उनके पास ऊर्जा नहीं बची है। उन्होंने कहा कि तिब्बती जनता भी शांति से जीवन गुजारना चाहती है बशर्ते कि उनको सार्वभौमिक आज़ादी और स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन खुद को जलाकर मरना पसंद कर रहे हैं क्योंकि चीन सरकार द्वारा तिब्बत पर कब्जा और तिब्बतियों का दमन जारी है। उन्होंने कहा कि तिब्बत का दु:ख इतना स्पष्ट है कि चीन सरकार या चीनी जनता अब किसी भी तरह से यह बहाना नहीं बना सकती कि तिब्बत में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा, "उन्हें सांसदों के अंतरराष्ट्रीय समूह और विशेषज्ञों के बार–बार किए जाने वाले इस अनुरोध पर गौर करना चाहिए कि तिब्बत में अबाधित और अनियंत्रित तरीके से एक तथ्यान्वेषी दल को यात्रा करने की इजाजत दी जाए। ◆

तिब्बत में एक और सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बना रहा है चीन

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 5 अगस्त)

चीन ने 4 अगस्त को कहा कि वह तिब्बत में दुनिया के सबसे ऊंचे अक्षांश पर एक और नागरिक एयरपोर्ट बना रहा है। करीब 4,441 मीटर ऊंचाई पर स्थित दाओछेंग याडिंग एयरपोर्ट सिचुआन प्रांत के गार्जी प्रशासनिक क्षेत्र में बनाया जा रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ की खबर के मुताबिक यह नया एयरपोर्ट इसके पहले निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे बांगदा एयरपोर्ट को ऊंचाई के मामले में पीछे छोड़ देगा। बांगदा एयरपोर्ट तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के क्वामदो प्रशासनिक क्षेत्र स्थित बांगदा टाउन में स्थित है। बांगदा एयरपोर्ट की समुद्र तल से ऊंचाई 4,334 मीटर है।

फिलहाल चीन तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में पांच नागरिक एयरपोर्ट बना चुका है जिनके नाम गोंगार (ल्हासा एयरपोर्ट), बांगदा, शिगाजे, एली और लिंगझी हैं। इसके अलावा उत्तरी तिब्बत के नांगछू प्रशासनिक क्षेत्र में भी उसकी एक एयरपोर्ट बनाने की योजना है। चीनी कब्जे वाले तिब्बत के अन्य इलाकों में भी चीन सरकार ने कई एयरपोर्ट बनाए हैं जिनमें युशु प्रशासनिक क्षेत्र, क्विंघई प्रांत के गोलमुद और शीनिंग शहर में, सिचुआन प्रांत के नाबा प्रशासनिक क्षेत्र और यून्नान प्रांत के डेछेन प्रशासनिक क्षेत्र के शांग्री–ला काउंटी में बने एयरपोर्ट शामिल हैं।

पीटीआई समाचार एजेंसी की 4 अगस्त की खबर के मुताबिक तिब्बत में हवाई यातायात ढांचे के तीव्र विकास के अलावा तेजी से रेलमार्गों और सड़कों के विकास ने भारत को चिंतित कर दिया है क्योंकि इनसे चीनी सैनिकों को सीमावर्ती इलाकों में तेजी से अपनी टुकड़ियों और साजो–सामान को भेजने में आसानी होगी। बांगदा एयरपोर्ट को मरम्मत के लिए 22 जून को बंद कर दिया गया था और 5 अगस्त को इसे फिर से खोल दिया गया। ◆

भारत ने अधिकृत तिब्बत में बने रहे चीनी बांध पर चिंता जताई

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 14 अगस्त)

भारत ने गत 12 अगस्त को कहा कि तिब्बत में यारलुंग सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर चीन द्वारा तीन बांध बनाने को मंजूरी देने पर उसने चीन सरकार को अपने "विचार और चिंताएं" बता दी हैं। इन बांधों से निचली धाराओं के पास स्थिति भारतीय क्षेत्र के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका है। भारत के जल संसाधन मंत्री श्री हरीश रावत ने संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि वह चीन से पहले ही यह अनुरोध कर चुके हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि निचली धाराओं के पास स्थित देशों के हितों को कोई नुकसान न हो। मंत्री ने संसद को बताया कि हाल में रिलीज "चीन जनवादी गणतंत्र के राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास की 12वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा" से ऐसे संकेत मिले हैं कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्यधारा पर तीन बांध परियोजनाएं बनाने को चीनी प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2011 से 2015 तक चलेगी। रावत ने कहा कि भारत के इससे प्रभावित होने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार ने क्रमशः 11 अक्टूबर 2010, 15 जून 2011 और 27 फरवरी 2012 को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस विकास पर अपनी गहरी चिंता जताई है। गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिमी तिब्बत के गारी प्रशासनिक क्षेत्र स्थित पुरांग काउंटी से निकलती है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले दक्षिणी तिब्बत में हिमालय के समानांतर बहती है। ◆

तिब्बत में धार्मिक समारोह में चीन ने किए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 9 अगस्त)

तिब्बत की राजधानी ल्हासा के ड्रेपंग मठ में 6 अगस्त को शोटोन धार्मिक समारोह शुरू हुआ जिसमें चीनी प्रशासन ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त कर रखे थे। इस समारोह में धार्मिक परंपरा के तहत भिक्षुओं को लोग खाने के लिए योगर्ट (दही के साथ एक डिश) पेश करते हैं। इस समारोह में शामिल होने वाले तिब्बतियों को स्कैनर से होकर गुजरना पड़ रहा था और आसपास भारी संख्या में अर्द्धसैनिक सशस्त्र बल और पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। सुरक्षा बलों की तैनाती एक दिन पहले ही कर दी गई थी और खासकर उस जगह विशेष चौकसी बरती जा रही थी जहां मठ के पहाड़ी चोटी पर बुद्ध की एक विशाल मूर्ति का अनावरण होना था और भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। मठ के दोनों तरफ प्रवेश द्वारों पर स्कैनर लगाए गए थे और समारोह में शामिल होने के जाने वाले हर व्यक्ति को इन स्कैनर से होकर गुजरना पड़ता था। रेडियो फ्री एशिया (आरएफए, वाशिंगटन) ने 7 अगस्त को एक स्थानीय तिब्बती सूत्र के हवाले से बताया कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित ड्रेपंग मठ में परंपरागत तरीके से होने वाले इस समारोह में इस साल सुरक्षा बलों की मौजूदगी पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। सूत्र ने कहा, "मठ के प्रांगण में धातु के बैरीकेड लगाए गए थे और लोगों की एक–एक कर गहन तलाशी ली जा रही थी।"

खबर में एक और गवाह के हवाले से बताया गया है कि इस साल समारोह में जितने श्रद्धालु आए थे, लगभग उतने ही तो सुरक्षा बल भी थे। शोटोने समारोह की शुरुआत 17वीं शताब्दी में एक धार्मिक आयोजन के रूप में हुई थी, जब आम तिब्बतियों ने उन बौद्ध भिक्षुओं को योगर्ट पेश किया था जो अपना सालाना ध्यान कार्यक्रम पूरा करने के बाद वापस आए थे। इस परंपरा की शुरुआत भारत में शताब्दियों पहले गौतम बुद्ध के समय हुई थी। पिछले कुछ वर्षों से चीन इस समारोह को प्रमुख पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रचारित कर रहा है। यह समारोह 6 से 14 अगस्त तक चलता है और इसके दौरान विभिन्न तरह के धार्मिक कलाएं, एक व्यापार मेला, फोटो प्रदर्शनी, साइकिल दौड़ और परंपरा के मुताबिक नोर्बुलिंगा महल मैदान में एक तिब्बती ओपेरा का प्रदर्शन किया जाता है। इन सभी का थीम होता है, "खुश ल्हासा, सुंदर घर"। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने 6 अगस्त को खबर दी है कि इस साल शोटोन में एक रिकॉर्ड

संख्या में चीनी और विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। इस साल ल्हासा में 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच 9,06,400 यात्री आ रहे हैं जो पिछले साल के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा है। वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत का कहना है कि चीन की सरकारी मीडिया ने सुरक्षा बलों की मौजूदगी को कहीं–कहीं ही दिखाया है और उनका जोर मुख्यतः भीड़ दिखाने और लोगों के आकर्षण एवं समर्पण, विशाल थांगका पेंटिंग दिखाने पर है।

संगठन ने कहा कि 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के शुरुआत में कुछ तिब्बतियों ने इस समारोह के दौरान विरोध प्रदर्शन किए थे। संगठन ने कहा, "वर्ष 1993 में तिब्बती झंडा लहराते चार भिक्षुओं ने "दलाई लामा जिंदाबाद" के नारे लगाए थे और इसके पिछले पांच साल में शोटोन समारोह के दौरान वे ऐसा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले तीसरे समूह थे। वर्ष 1990 में मेछुंगरी और गारू भिक्षुणी मठ के 12 तिब्बती भिक्षुणियों को ड्रापची जेल में कठोर कारावास की सजा दी गई थी। इन भिक्षुणियों ने शोटोन समारोह के दौरान नोर्बुलिंगका महल पर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था। नोर्बुलिंगका महल दलाई लामा के गर्मियों के दौरान रहने के लिए बनाया गया है। ◆

दलाई लामा शांति के योद्धा

(तिब्बत डॉट नेट, धर्मशाला, 8 अगस्त 2013)

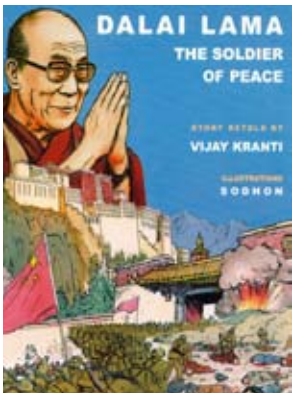

धर्मशाला 'दलाई लामा शांति के योद्धा' एक कॉमिक पुस्तक है। यह माननीय 14वें दलाई लामा की जीवनी है। इस जीवनी को प्रतिष्ठित लेखक और पत्रकार श्री विजय क्रांति ने तैयार किया है। कॉमिक पुस्तक को 7 अगस्त को धर्मशाला में एक छोटे समारोह में जारी किया गया। यह कॉमिक पुस्तक सभी उम्र के पाठकों के लिए पठनीय है और यह पुस्तक चीन के कब्जे के दौरान मारे गए 12 लाख तिब्बतियों और दुनिया भर में फैले तिब्बत समर्थक समूहों के कठिन कार्यों को समर्पित है।

इस पुस्तक में यह बताया गया है कि किस प्रकार तिब्बत के भिक्षुओं ने पूर्व दलाई लामा के पुनर्जन्म को ढूंढा, तिब्बत और चीन के बीच क्या संबंध है, किस प्रकार से तिब्बत पर कब्जा किया गया, किस प्रकार से दलाई लामा भागे और वे कौन सी बातें हैं, जो वर्तमान दलाई लामा को वर्तमान मानव इतिहास की सबसे चर्चित और लोकप्रिय हस्ती बनाती है।

लेखक कहते हैं कि दलाई लामा की कहानी अनेक बार कही जा चुकी है, फिर भी उनकी कहानी को बार–बार सुनाया जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांति और अहिंसा की ताकत को साबित करने में दलाई लामा के योगदान को रेखांकित करता है।

उन्होंने कहा कि दलाई लामा के दिए गए संदेशों को दुनिया भर में न्याय के लिए संघर्ष कर रहे सैकड़ों समुदायों ने अपनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अपनी कॉमिक पुस्तक के माध्यम से वह लोगों के अंदर प्यार और सहानुभूति की भावना जगा पाएंगे।

माननीय दलाई लामा को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है और वे सामाजिक सद्भाव के संदेशवाहक हैं। उन्होंने शांति और अहिंसा के अपने संदेश से दुनिया भर में हजारों लोगों को अनुप्राणित किया है। उनकी कहानी दुनिया भर में बार–बार दुहराई जाती रही है। शांति, प्यार और सद्भाव का उनका संदेश एक वैश्विक घटनाक्रम है, जो झगड़ों से भरी दुनिया में अधिकाधिक प्रासंगिक होती जा रही है।

श्री विजय क्रांति एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और तिब्बत विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तिब्बत मुद्दे पर दर्जन भर से अधिक फोटो प्रदर्शनी लगाई है। उन्होंने दलाई लामा पर और भी पुस्तकें लिखी हैं। उनमें शामिल हैं– कॉफी टेबल पुस्तक 'दलाई लामा स्पीक्स' और दलाई लामा की जीवनी 'फ्रीडम इन एक्साइल' का हिंदी संस्करण। ◆

नेपाल में एक साल में तिब्बती आत्मदाह की दूसरी घटना में भिक्षु की मौत

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 7 अगस्त, 2013)

एक युवा तिब्बती भिक्षु ने गत 6 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आत्मदाह करने से मौत हो गई। यह घटना सुबह 7.30 बजे के करीब शहर के पूर्वोत्तर इलाके में स्थित बौद्धनाथ स्तूप के पास की है। करीब 39 वर्ष के इस युवा भिक्षु का नाम कर्मा नेधोन ग्यात्सो है और वह हाल में ही तिब्बत की राजधानी ल्हासा में स्थित काउंटी डामसुंग से निर्वासित होकर नेपाल आए थे। यह एक साल नेपाल में आत्मदाह की दूसरी घटना है। ऐसी पहली घटना में इस साल फरवरी में इसी इलाके में ड्रुबछेन सेरिंग नाम के भिक्षु ने आत्मदाह कर लिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवा भिक्षु पालथी मारकर बैठे, एक घी का दीया जलाया, उसे अपनी गोंद में रखा, कुछ प्रार्थनाएं कीं और इसके बाद एक बोतल में लाए ज्वलनशील पदार्थ को अपने ऊपर गिरा लिया। समाचार एजेंसी एपी की 6 अगस्त की खबर के मुताबिक पुलिस ने बताया कि घटना एक गली में हुई और आसपास कोई नहीं था। मिनटों में ही आग की लपटों में घिर चुके भिक्षु को तत्काल त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार नेपाल पुलिस ने आत्मदाह से मौत की इस घटना के बाद स्थानीय तिब्बती समुदाय के लोगों को बुलाकर "पूछताछ" की। हालांकि, उसी दिन हिंदुस्तान टाइम्स डॉट कॉम की एक खबर में बताया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने यह दावा किया कि उस भिक्षु की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इस मौत का तिब्बतियों के अपने देश या उससे बाहर किए जा रहे आत्मदाह के सिलसिले से कोई रिश्ता नहीं है।

जुलाई 2013 में नेपाल पुलिस ने ऐसी घटनाओं को रोकने और तिब्बत से आने वाले तिब्बतियों पर नजर रखने के लिए बौद्धनाथ स्तूप के आसपास 35 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। खबर के अनुसार इस भिक्षु ने जनवरी 2012 में तिब्बत की सीमा पार कर नेपाल में प्रवेश किया था और भारत की यात्रा करने के बाद फिर से नेपाल चले आए थे।

यह नेपाल में तिब्बतियों द्वारा अब तक किया जाने वाला तीसरा आत्मदाह है। इनमें से दो तिब्बतियों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले नवंबर, 2011 में भुटोक नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने आत्मदाह कर लिया था। आसपास मौजूद लोगों के तत्परता से कार्रवाई करने की वजह से वह बच तो गए लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके पहले नेपाल में छपी खबरों के अनुसार दूसरी बार आत्मदाह की घटना होने पर चीन ने नेपाल को डांट पिलाई थी। ◆

चीनी सैनिकों ने भारतीयों को भारतीय सीमा में ही गश्त करने से रोका

(तिब्बननरीव्यू डॉट नेट, 05 अगस्त, 2013)

भूमि और हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण करने के बाद चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को सीमा पर उकसाने का एक नया तरीका अपनाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की चार अगस्त की रपट के मुताबिक वे भारतीय सैनिकों को अपनी ही सीमा के अंदर गश्त करने से रोक रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी एक ताजा घटना एक सप्ताह पहले हुई जब भारतीय सैनिकों ने लद्दाख के उत्तर में स्थित ट्रेड जंक्शन क्षेत्र से 14 किलोमीटर आगे ऊंचाई पर स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दो पोस्ट के लिए गश्त शुरू किया। रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने चार अगस्त को कहा कि भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ने से रोक दिया। वे हल्के और भारी वाहनों पर भारतीय सीमा में घुसे थे। सूत्रों ने कहा कि भारतीय पेट्रोल पार्टी को बैनर दिखाए गए, जिसमें लिखा था कि वे चीन की सीमा में हैं और आगे पोस्ट तक नहीं जा सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के जवान अपने पोस्ट पर थे, लेकिन चीनी सैनिकों का रवैया आक्रामक था।

रिपोर्ट के मुताबिक वे पोस्ट भारतीय सीमा के बिल्कुल अंदर थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस साल अप्रैल के बाद से भारतीय सैनिकों ने उन पोस्ट के लिए 21 बार गश्त शुरू की, लेकिन वे गंतव्य तक सिर्फ दो बार ही पहुंच पाए।

रिपोर्ट के मुताबिक चीनियों ने एक निगरानी पोस्ट खड़ा कर लिया था, जिससे वे भारतीय सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और जैसे ही भारतीय गश्त पार्टी रवाना होने के लिए तैयार होती वे आगे आकर रास्ता रोक लेते और उन्हें वापस भेज देते। भारत ने चुसुल में होने वाली अगली सीमा कर्मी बैठक (बीपीएम) में इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक इसी लद्दाख क्षेत्र में ऐसे भी मामले आए हैं, जब चीनी सेना के वाहनों को देसपांग बल्ज और दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) में देखा गया, जहां इस साल 15 अप्रैल से 21 दिनों दोनों सैनिकों के बीच स्थिति तनाव पूर्ण थी। वास्तव में अभी भी चीनी सैनिक नियमित तौर पर भारतीय क्षेत्र में घुसते पाए गए हैं।

भारत के ब्रिगेडियर संजीव राय ने उदाहरण देकर कहा है कि 16 और 19 जुलाई को चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 1.2 किलोमीटर भीतर तक घुस गए थे। वे 17 जुलाई को भी 2.5 किलोमीटर, 20 जुलाई को 200 मीटर अंदर आक्रामक गश्त के रूप में और 25 तथा 26 जुलाई के बीच की रात को 3.5 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि ये अतिक्रमण मुख्यतः लद्दाख की राजधानी लेह से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुमार और देमचोक में हुए।

रिपोर्ट में भारतीय सूत्रों के हवाले से कहा गया कि चीनी सैनिकों का आक्रामक व्यवहार चिंता की बात है और 15 अप्रैल के बाद डीबीओ सेक्टर पर उपजी तनावपूर्ण स्थिति के बाद से देखा जा रहा है। ◆

दलाई लामा से संपर्क रखने के नाम पर चीन ने तिब्बती मठ को बंद किया

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 4 अगस्त, 2013)

चीन ने उत्तरी तिब्बत के नागछू काउंटी में स्थित एक बौद्ध मठ को बंद करने का आदेश दिया है क्योंकि उसके निर्वासित आध्यात्मिक तिब्बती नेता दलाई लामा से गहरे संपर्क हैं। धर्मशाला स्थित तिब्बती प्रशासन ने अपनी वेबसाइट तिब्बत डॉट नेट पर 3 अगस्त को यह जानकारी दी है। वेबसाइट ने बताया है कि मठ को बंद करने के आदेश के बाद शाकरोंगपो स्थित गादेन धार्गेलिंग मठ के पास सैंकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बंद कर दिए गए मठ के भिक्षुओं ने आसपास के कई जगहों पर शरण ली है। निर्वासित प्रशासन ने कहा है कि मठ पर चीनी प्रशासन की दमनात्मक कार्रवाई वर्ष 2010 में ही शुरू हो गई थी, जब चीनी अधिकारियों ने यह आरोप लगाया था कि मठ के भिक्षु अपने आध्यात्मिक प्रमुख रोंगपो छोएजे रिनपोछे के पुनर्जन्म की पहचान में दलाई लामा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब 78 वर्ष के हो चुके एक महत्वपूर्ण भिक्षु लामा दावा को तब गिरफ्तार कर लिया गया था और कई तरह के आरोप लगाकर सात साल के लिए जेल में डाल दिया गया। उनके फिर मठ में शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कई अन्य भिक्षुओं को गिरफ्तार कर विभिन्न तरह के आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। लामा दावा का फिलहाल प्रशासन की सख्त निगरानी में एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इसके अलावा, चीनी अधिकारियों द्वारा भिक्षुओं पर भारी अत्याचार से दुःखी होकर एक 75 साल के भिक्षु गवांग ग्यात्सो के आत्मदाह कर लेने की खबर है। बताया जाता है कि चीनी अधिकारी भिक्षुओं पर लगातार इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वे दलाई लामा और अन्य प्रमुख तिब्बती आध्यात्मिक हस्तियों की निंदा और भर्त्सना करें, जिसकी वजह से भिक्षुओं को असहनीय पीड़ा और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। ◆

चीन के एपल सप्लायर कारखानों में तिब्बतियों की भर्ती पर रोक

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 31 जुलाई, 2013)

अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एपल के लिए उत्पाद बनाने वाली चीन की कई फैक्टरियों की नियुक्ति प्रक्रिया में तिब्बतियों सहित अन्य अल्पसंख्यक समूह के साथ भेद–भाव किया जाता है। यह बात अमेरिका स्थित 'चीन लेबर वाच' ने 29 जुलाई को प्रकाशित अपनी जांच रिपोर्ट में कही। यह रिपोर्ट ताइवान के पेगाट्रॉन समूह की तीन फक्टरियों की जांच पर आधारित है और इसमें आरोप लगाया गया है कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अल्पसंख्यकों की नियुक्ति नहीं की जाती है।

श्रमिक अधिकार संगठन ने कहा कि कम से कम 86 मामलों में श्रम अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसके तहत पेगाट्रॉन समूह ने 36 कानूनी उल्लंघन और 50 नैतिक उल्लंघन किए। पेगाट्रॉन समूह एपल की एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इन फैक्टरियों में आईफोन 4, आईफोन 4एस और आईफोन 5 जैसे उत्पादों की एसेंबलिंग की जाती है।

नागरिक अधिकार संगठन ने कहा कि उनके जांचकर्ता शंघाई और उसके पास स्थित सुझो शहर में स्थित फैक्टरियों में जांच करने गए। इनमें 70 हजार लोग काम करते हैं और इनमें इस साल मार्च से जुलाई के बीच करीब 200 साक्षात्कार हुए।

यही नहीं, लंदन स्थित एक अन्य संगठन फ्री तिब्बत ने भी 29 जुलाई को अपने वेबसाइट पर एक पोस्टर प्रकाशित किया, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार अन्य राष्ट्रीयता वाले अभ्यर्थियों के साथ भेद–भाव होता है। पोस्टर का अनुवाद कुछ इस प्रकार है – ''अलग जीवनशैली और रीति रिवाजों वाले हुई, सालार, यी, तिब्बती, उइगर, आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।''

फ्री तिब्बत ने तिब्बतियों के हवाले से कहा है कि तिब्बतियों के साथ हमेशा भेद–भाव किया जाता है और यह भेद–भाव चीन द्वारा कब्जा किए गए तिब्बत और चीन के दूसरे हिस्सों दोनों ही क्षेत्रों में रहने, यात्रा करने या नौकरी खोजने के समय होता है। ◆

तिब्बतियों की स्वायत्तता की स्थिति ने हांगकांग पर भी सवाल खड़ा किया

(माइकल सी.डेविस, साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट)

चीन के तथाकथित स्वायत्तता की नीतियों के विरोध में तिब्बतियों के 120वें आत्मदाह के बाद हांगकांग की जनता (जिन्हें खुद स्वायत्तता की गारंटी दी गई है) को यह जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर तिब्बती इतने असंतुष्ट क्यों हैं। इससे चीन और निर्वासित तिब्बती नेताओं को एक समाधान खोजना होगा। वर्ष 1951 में सात बिंदुओं वाले समझौते में जिसे कभी–कभी हांगकांग के समझौते का पूर्ववर्ती रूप माना जाता है, बीजिंग ने यह वायदा किया था कि चीनी प्रभुसत्ता के साथ ही तिब्बती भी अपना स्वशासन जारी रख सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ही कम्युनिस्ट शासन के दौरान जिस तरह से अत्याचार हुआ, उससे यह समझौता चिंदी–चिंदी हो गया और 1959 में दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद चीन ने "अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता स्वायत्तता" की घोषणा की। तिब्बत को 13 स्वायत्तशासी क्षेत्रों में बांट दिया गयाः तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र और पड़ोसी प्रांतों के 12 अन्य क्षेत्र। तिब्बत की समस्या इसी वजह से है क्योंकि सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक स्वायत्तता कानून को पूरी तरह से लागू करने में विफल रही है और उसने प्रतिरोध बनाए रखने के लिए दमनकारी नीतियों का सहारा लिया है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए काफी पहले ही दलाई लामा अपने "मध्यम मार्ग" नीति के तहत स्वायत्तता के समर्थन में आज़ादी का दावा छोड़ना स्वीकार कर चुके हैं। वर्ष 2008 के खून–खराबे के बाद उन्हें इस बात के लिए आमंत्रित किया गया था कि वह चीन जनवादी गणतंत्र के तहत अपना प्रस्ताव पेश करें, जिसे उन्होंने 2008 में तिब्बती जनता के लिए वास्तविक स्वायत्तता के ज्ञापन के रूप में किया भी था। इसमें कहा गया था कि स्वशासन, भाषा, संस्कृति, धर्म, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में वास्तविक स्वायत्तता होनी चाहिए। इससे काफी हद तक चीन की मौजूदा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रतिबद्धता भी पूरी होती और आव्रजन, जनसुरक्षा पर उसका नियंत्रण भी रहता जैसा कि हांगकांग में है।

लेकिन इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज करते हुए चीन ने यह तर्क दिया कि इसमें "बहुत ज्यादा स्वायत्तता" की मांग की जा रही है और यह तो "आज़ादी" के समान है। इस पर चीन सरकार ने कुछ नहीं कहा है कि आखिर इसी तरह की "उच्च स्तर की स्वायत्तता" हांगकांग को देने के बावजूद उसको आज़ादी देना क्यों नहीं माना जाता। ऐसा लगता है कि तिब्बत को स्वायत्तता देने की प्रतिबद्धता भरोसे की कमी की वजह से खोखली हो गई है। चीन को इस बात की चिंता है कि "वास्तविक स्वायत्तता" असल आज़ादी की ओर बढ़ने का पहला कदम हो सकता है। आज तक लगातार दुःखद अनुभव करने के बाद तिब्बती पक्ष निश्चित रूप से किसी ठोस गारंटी के बिना किसी आधार पर सहमत होने में संदेह की नजर से ही देखेगा। चीन इस बात के लिए भी दबाव बनाता रहा है कि दलाई लामा उसके इस काफी विवादास्पद दावे को मान लें कि तिब्बत हमेशा से ऐतिहासिक रूप से चीन के शासन के तहत ही रहा है। दलाई लामा सिर्फ यह स्वीकार करते हैं कि चीन के साथ तिब्बत के ऐतिहासिक शाही रिश्ते रहे हैं। उनके लिए स्वायत्तता इन कठिन परिस्थितियों में उपलब्ध एक मात्र व्यावहारिक विकल्प है। यहां तक कि यदि चीनी नजरिये का इतिहास देखें तो तिब्बत को पूरे शाही साम्राज्य के दौरान वास्तविक स्वायत्तता मिलती रही थी, जब सीमांत बाहरी इलाकों में अप्रत्यक्ष शासन का चलन था। तिब्बती ज्ञापन पर गहराई से नजर डालने पर पता चलता है कि इसमें न केवल चीन की अपनी घोषित नीतियों का ध्यान रखा गया है, बल्कि 2007 में मूल निवासियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक के भी अनुरूप है, जिसका उद्देश्य मूल निवासियों को स्वशासन और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करना है। चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन तत्काल ही उसने यह भी दावा किया कि चीन में कोई भी मूल निवासी नहीं है।

हो सकता है कि चीन के दीर्घकालिक हित इस बात से ज्यादा सधते हों कि वह अंतरराष्ट्रीय मानक का मुंह चिढ़ाए। स्वायत्तता का मतलब है कि तिब्बत में कम से कम दखल, जो कि चीन शायद हांगकांग में भी नहीं करना चाहता है। दलाई लामा के साथ समझौते को तिब्बतियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का पूरा समर्थन मिल सकता है।

(हांगकांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल डेविस संवैधानिक विशेषज्ञ हैं) ◆

भारतीय पहाड़ों के लिए नया बल

cãk pykuh

(द वॉल स्ट्रीट जर्नल, 1 अगस्त, 2013)

भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन से लगने वाली हिमालयी सीमा की रक्षा के लिए एक "माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स" (पर्वत हमला बल) के गठन की घोषणा की है। एक्शन फिल्मों जैसे नाम और 50,000 जवानों वाला यह बल शायद इन गर्मियों में चीन द्वारा लगातार सीमा अतिक्रमण की घटनाओं का भारत की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया की तरह है। लेकिन यह घोषणा फिर से यह साबित करती है कि चीनी आक्रामकता के जवाब में भारत की रणनीति कितनी भीरू किस्म की है। चीनी सेना का हिमालय अभियान दक्षिण और पूर्वी चीन में उसके नौसैनिक आक्रामकता का छद्म प्रतिरूप है। चीन असल में "सलामी स्लाइसिंग (सलामी गोश्त के काट कर टुकड़े करना) रणनीति पर पर आगे बढ़ रहा हैं इसके तहत लगातार कई छोटे–छोटे कदमों को आगे बढ़ाया जाता है, इनमें से कोई अकेले युद्ध को न्यायोचित ठहराने का काम नहीं करता, बाद में यह चीन के पक्ष में एक रणनीतिक रूपांतरण साबित होता है। अपने आकार और क्षमताओं के बावजूद नाभिकीय हथियारों से लैस भारत इस रणनीति की प्रतिक्रिया में पक्षाघात से ग्रस्त हो गया है। एक बार फिर श्री सिंह की घिरी हुई सरकार ने मुकाबले का बदले रियायत देने का विकल्प चुना है, जैसे लगता कि भारत के पास खुशामद करने या पुरजोर लड़ाई लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। यह कमजोरी अप्रैल और मई में साफतौर पर दिखी जब चीनी सेना ने भारत के लद्दाख इलाके में जमीन पर कब्जा जमा लिया। चीन ने सैनिकों ने इस जमीन पर बनाया अपना टेंट वगैरह तब ही हटाया जब तीन हफ्ते की बातचीत के बाद भारत ने एक तरह से लगभग आत्मसमर्पण ही कर दिया। इस क्षेत्र से चीनी सैनिकों के हटने के बदले में भारत को वहां पर कोई कब्जा नहीं मिला, भारत ने लद्दाख के चुमार इलाके में अपने प्रतिरक्षा के लिए तैयार निर्माण कार्य नष्ट कर दिये और इस इलाके में गश्त भी रोक दी गई। भारत ने इस बात पर भी हामी भरी कि वह चीन द्वारा तैयार "सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते" पर विचार करेगा।

यह समझौता 1993, 1996 और 2005 के ज्यादा न्यायसंगत सीमा समझौतों की जगह लेगा, जिससे क्षेत्रीय विवाद के मामले में चीन के इस पसंदीदा रवैये की पुष्टि होगीः जो भी हमारा है वह हमारा है और जो आपका है उस पर बातचीत होनी चाहिए. एक रक्तरंजित जीत हासिल करने के बाद से ही उत्साहित चीन हमेशा अपने दांव ऊपर ही रखता है. उसके सैन्य उकसावे की कार्रवाई में पूरे हिमालयी सीमा पर लगातार छापेमारी और अन्य आक्रामक कदम शामिल हैं। गत 17 जून को चीन की जनमुक्ति सेना ने चुमार पर धावा बोल दिया और भारतीय निगरानी चौकी और अन्य साजो–सामान को नष्ट कर दिया, वे अपने साथ सुरक्षा कैमरा भी लेकर चले गए।

भारत सरकार ने तीन हफ्ते तक चीन की इस छापेमारी को छुपाकर रखा इस डर से कि कहीं जुलाई के शुरुआत में रक्षा मंत्री के चीन दौरे को निरस्त करने का जनदबाव न बढ़ जाए। इस दौरे के बावजूद अगस्त महीने में पीएलए द्वारा चुमार में चार बार घुसपैठ की खबर मिली है। अपनी इस कायरता को छुपाने के लिए श्री सिंह की सरकार माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के गठन पर इतरा रही है–जिसका गठन तो कई साल पहले ही बिना मीडिया प्रचारबाजी के हो जाना चाहिये था। चीन अपनी क्षमताओं को शांति से विकसित कर रहा है और सैनिकों की तैनाती कर रहा है, जबकि भारत सरकार अपने किसी छोटे से प्रतिरोध कदम को भी खूब प्रचारित करती है।

नए स्ट्राइक कॉर्प्स के गठन के लिए भारत को कई साल लग जाएंगे। मनमोहन सिंह ने अपनी पहचान बन चुके दब्बूपन के साथ देश के साथ धोखा कर ही चुके हैं, यह निर्णय लेकर इस बल की तैनाती अचानक चीनी सैन्य हमले के लिए नाजुक माने जाने वाले इलाकों में नहीं–जैसे अरुणाचल प्रदेश, जिस पर 2006 से चीन अपना दावा करता है, बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम जैसे उन इलाकों में किया जाएगा, जिनकी सीमा चीन से लगती ही नहीं है। भारत सरकार ने चीन को इस बात की इजाजत दी है कि वह द्विपक्षीय रिश्तों के लिए शर्तें खुद बताए।

भारत को अपनी हिमालय नीति के तहत सबसे पहले (और शांति से) अपने हमलावर बलों को नाजुक इलाकों में तैनात करना चाहिए। इनमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख शामिल हैं जो हिमालय के दो छोरों पर स्थित सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्ध इलाके हैं। ये इलाके भारतीय सेना के लिए अपरिचित इलाके नहीं हैं। वास्तव में श्री सिंह द्वारा वर्ष 2010 में सैन्य बलों की जगह सीमा पुलिस की तैनाती की वजह से ही चीन को घुसपैठ करने का मौका मिला है।

दूसरा, भारत सरकार को भविष्य में किसी तरह की बातचीत के लिए हाल के सीमा समझौते को आधार मानने की बात तत्काल खारिज करना चाहिए। लेकिन फिलहाल भारत तो इसका उलटा कर रहा है, चीन द्वारा थोपे गए प्रारूप समझौते पर टिप्पणियां और सुझाव दे रहा है। बीजिंग में भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी एक संयुक्त बयान पर राजी हो गए जिसमें भारत ने चीनी प्रारूप के ऊपर "बातचीत में जल्दी कोई निष्कर्ष निकालने पर हामी भरी।"

भारत को इसकी जगह परस्पर सम्मान वाले एक ऐसे समझौते को आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें क्षेत्रीय सीमा और नदी जल प्रवाह पर यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए। आखिरकार चीन न केवल नियंत्रण रेखा में बदलाव चाह रहा है बल्कि सीमा पार तक बहने वाली नदियों पर तमाम बांध बनाकर उनकी धाराओं को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। निचली जलधारा पर स्थित एक देश होने के नाते भारत पर जलयुद्ध का खतरा खासतौर से मंडरा रहा है। भारत में हर साल 300 अरब डॉलर क्यूबिक मीटर से ज्यादा सतह जल सीधे चीनी क्षेत्र से आता है। भारत की मौजूदा चीन नीति यह दिखाती है कि किस तरह से दब्बू लोगों को लोग डराते–धमकाते हैं। भारत जितना डरेगा चीन उतना ही लड़ाकू रुख दिखाएगा। जब तक भारत में ऐसी सरकार नहीं आती जो देश के अधिकारों की रक्षा करने की इच्छा रखती हो, चीन ऐसे ही सीमा पार अतिक्रमण करता रहेगा ताकि नया जमीनी तथ्य तैयार कर सके और साझी नदियों के संसाधनों के दोहन के लिए बांध बनाता रहेगा।

(ब्रह्मा चेलानी इंडीपेन्डेंट सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सामरिक अध्ययन के प्रोफेसर हैं) ◆

तिब्बती सेनानी

frCcrh vknkyudkjh vkj y[kd ruftu lM, viu y[ku vkj gky d o"kk e 'k: g, vkRenkg d ygj d ckj e crk jg g

ruftu lM,] ikmMj e vkidk Lokxr gA ge vki tl i[;kr y[kd vkj Lor=rk lukuh l ckrphr dj lEekfur egll dj jg gA

धन्यवाद। यह मेरे लिए भी एक सम्मान की बात है। हमारी आवाज नए और व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद।

Ok"k 1997 e vki frCcr e x, Fk vkj vkidk ogk d i'kklu u tyk e Mky fn;kA frCcr d ckj e vkid eu e D;k Nfo g\ vkidk dn fdl rjg l fd;k x;k vkj vkidk dn e vuHko dlk jgk\

जब मैं बेतरतीब फैल रहे ल्हासा शहर पहुंचा तो यह देखकर मेरे मन में बनी छवि ध्वस्त हो गई कि शहर में हर तरफ बड़ी संख्या में चीनी दिख रहे हैं। मुझे कैदी की तरह घुमाया गया और 7वीं शताब्दी के ऐतिहासिक राजधानी भवन पोटाला महल के सामने खड़ाकर पुलिस वालों ने रिकॉर्ड के लिए मेरी फोटो खींची। ज्यादातर दुकानें, कार्यालय और इमारतें चीनियों के थे और यहां तक कि शिगास्ते और ल्हात्से जैसे छोटे शहरों में भी ऐसा ही हाल था। तिब्बत में रहने और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की मेरी योजन धरी रह गई। मैं तिब्बत में पांच दिन नही घूमा था कि मुझे इस संदेह पर गिरफ्तार कर लिया गया कि मैं भारत द्वारा जासूसी अभियान पर भेजा गया हूं। भारत की सीमा के करीब तिब्बत के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में स्थित नागरी कस्बे में 12 दिन तक जेल में रखने के बाद मुझे एक पुलिस कार में बिठाकर आगे की पूछताछ के लिए ल्हासा ले जाया गया। जेल में साथ रहने वाले मेरे तिब्बती साथियों को यह आशंका थी कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है और मुझे उन्होंने सलाह दी कि कुछ भी मैं अपने बयान पर कायम रहूं। मैंने तिब्बत जाने के अपने गोपनीय अभियान के बारे में किसी को नहीं बताया था और अब शहर के एक बाहरी इलाके में मुझे जेल में ठूंस दिया गया था, ऐसे में मैं पूरी तरह से असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन जब मेरे ऊपर लगा कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ तो तीन महीने जेल में रखने के बाद चीनी अधिकारियों ने मुझे तिब्बत से बाहर फेंक दिया। तब मैं सिर्फ 22 साल का था और मेरे जीवन के लिए एक क्रैश कोर्स की तरह था जिसने मुझे इस तरह का जुझारू बनाया जैसा कि आज मैं हूं।

Hkkjr e fuokl u e iyr&c<r vkidk thou dlk Fkk\

हाल तक जब मैंने विदेश में व्याख्यान में जाना शुरू किया, मुझे जीवन का जो भी अनुभव था वह भारत में मेरे प्रवासी जीवन का ही था। इसलिए मैं इसे कभी "भारत में जीवन" की तरह नहीं देखता था। यही एकमात्र दुनिया थी जिसमें हम रहते थे। लेकिन बचपन से, अपने दादा–दादी की कहानियों और गीतों से, बचपन के खेलों और जो भाषा हम बोलते थे, मेरे मन में चुपचाप एक अलग दुनिया उठ खड़ी हुई थी, एक मातृभूमि का सपना जिसे हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन एक दिन वहां लौटना था।

चलाती, यह बस मौजूद है। कविता अपनी शर्तों के साथ आती है और मेरे द्वारा लिखी जाती है और कभी–कभी आंदोलनकारी होने के नाते बैठकों में शामिल होने, नारे लगाने और लोगों को प्रशिक्षण देने या जेल व अदालत के मामले देखते समय मुझे कुछ ऐसी प्रेरणाएं मिल जाती हैं जिन पर आंख बंद कर विचार करता हूं।

vkidh dfork e, ,d foQyrk dk ln'k lekfgr gkrk g] yfdu ble mEehn dh ,d xgjh Hkkouk Hkh gkrh gA D;k vki ekurs g fd dyk ls jktuhrd Lrj ij fdlh rjg dk cnyko vk ldrk g\

मेरा मानना है कि कला असल में सच की लगातार तलाश ही है। इसकी भाषा, स्वरूप और आकार से मनुष्य को सबसे गहरे, लौकिक और सबसे गूढ़ मानवीय चिंताओं की जांच करने, प्रदर्शित करने और उन्हें अभिव्यक्त करने में मदद मिलती है। इसलिए राजनीतिज्ञ कला से डरते हैं, वे अक्सर कला को प्रतिबंधित कर देते हैं, क्योंकि कला से न केवल लोगों के सोचने का तरीका बदलता है, बल्कि यह क्रांति की भी वजह बन जाता है। तिब्बत में जिन तिब्बतियों को ज्यादा निशाना बनाया गया या गिरफ्तार किया गया, उनमें कवि, लेखक, गायक, कॉमेडियन और बुद्धिजीवी हैं।

frCcr iBkj ij phuh dCts d djhc 63 lky ckn] vkt frCcr dh D;k gkyr g\

करीब 1.2 करोड़ चीनी जनसंख्या की बाढ़ में 60 लाख तिब्बतियों की जनसंख्या डूब चुकी है। तिब्बत के 25 लाख वर्ग

हम तिब्बत के बारे में इतना जान गए थे कि हम उसके बाहर एक दुनिया बना सकते थे, एक समानांतर दुनिया। आज हम भारत में रह रहे हैं, लेकिन हमारा दिल वहीं रहता है। हम न तो यहां के हैं, न वहां के।

vkidh igyh iLrd ^Økfllx n ckMj^ ¼lhek ikj dh ;k=k½ dfork lxg FkhA vkidk o"k 2001 e x|j dFkk J.kh e igyk fidkMkj&vkmVyd vokM feyk vkj bld ckn l vkidh nk fdrkc vkbl g] dkjk vkj le'kdA vkidk y[ku 'k: dju dh ij.kk dgk l feyh\ vki viu y[ku l D;k gkfly djuk pkgr g\

मेरी जीवन में पहली सीख यह थी कि मैं उस देश में नहीं रहता हूं, जहां मेरा जन्म हुआ है और मेरे लिये विक्षुब्ध करने वाली बात थी। जब मैं पांचवीं कक्षा में था तब ही मैंने एक स्वतंत्रता सेनानी बनने का प्रण लिया। जब मेरे तिब्बती शिक्षकों ने लेखन और पत्रकारिता के बारे में बताया तो मैं भौतिक मार–काट के खिलाफ तर्कशक्ति की इस ताकत से काफी प्रभावित हुआ। मैं तेजी से बड़ा होना चाहता था और अपने लेखन से दलाई लामा की तिब्बत के बारे में दुनिया को जागरूक करने में मदद करना चाहता था। लेकिन जल्दी ही मुझे यह समझ में आ गया कि दुनिया की राजनीति काफी हद तक राष्ट्रीय और कारोबारी हितों पर निर्भर करती है और कोई भी तिब्बत के बारे में समझने को तैयार नहीं है।

आज मैं अपने मामले को समझाने के लिए लेखन कर रहा हूं और इतिहास के लिहाज से आंदोलन का दस्तावेज भी तैयार कर रहा हूं। मैं भारतीय अखबारों और पत्रिकाओं में लिखता रहा हूं और बाद में इनको संग्रहित कर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराऊंगा। मेरी चौथी किताब 'सेनगोल–स्टोरीज एंड पोयम्स ऑफ रेजिस्टेंस' (प्रतिरोध की कहानियां और कविताएं) वर्ष 2012 में आई है। मेरे लेखन का मेरी जीविका में भी कुछ हद तक हिस्सा है। इस कवि ने जो कुछ लिखा है उसे आंदोलन के द्वारा प्रकाशित और वितरित किया गया है। मुझे इससे थोड़ी ही आय होती है, लेकिन मेरी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। कवि आंदोनकारियों की भूख का शांत करता है।

लेकिन मेरी कविता कोई बहस नहीं

किलोमीटर इलाके में, जो पश्चिमी यूरोप के आकार के बराबर है, सोना, तांबा और लीथियम सहित विशाल प्राकृतिक संपदा होने की वजह से यह चीन के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। हाल में तिब्बत में एक सोने के खदान के धंसने की खबर आई थी और तिब्बत में ऐसे सैकड़ों खदान हैं। तिब्बत एशिया की कई महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है जिनसे एशिया की डेढ़ अरब से ज्यादा आबादी की जल की जरूरत पूरी होती है। चीन अब तिब्बत को अपनी मुख्य भूमि के साथ सात रेलवे नेटवर्क और सैकड़ों राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रांतीय राजमार्गों से जोड़ रहा है। यह चीन के विकास के लिए किया जा रहा है और तिब्बत में तो तिब्बती पाठ्यपुस्तकों की जगह अब चीनी पाठ्यपुस्तक ले रहे हैं। तिब्बती मठ और संस्कृति को प्रदर्शनी की वस्तु की तरह पेश किया जा रहा है। तिब्बती मठों में अब तीर्थयात्रियों से ज्यादा पर्यटक पहुंचने लगे हैं। तिब्बती नोमैड और किसानों की जमीनें बड़े भू माफियाओं के हाथों में चली जा रही है जो भारी वादे करते हैं और अंत में उन्हें मुर्गी के दड़बे जैसा घर बनाकर दे देते हैं। इस बात पूरा खतरा आ गया है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं तो अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की तरह तिब्बती भी खत्म हो जाएंगे।

lhD;kx ikr ds gkykr dh vki frCcr ls fdl rjg ls rqyuk djuk pkgsxs

पूर्वी तुर्किस्तान को चीनी उपनिवेशवादी भाषा में सीक्यांग नाम दिया गया है जिसका मतलब होता है, “नया मोर्चा”, इसी तरह तिब्बत को वे शीचांग कहते हैं जिसका मतलब है, “पश्चिमी बहुमूल्य घोड़ा”। समस्या की शुरुआत 1911 में हुई, जब चीन लंबे समय तक चलने वाले मांचुओं के साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ। अपनी “सत्ता की विरासत” का दावा करने के लिए नए चीन गणराज्य ने मंचूरिया के पूर्व उपनिवेशों जैसे मंगोलिया के बड़े हिस्से पर अपने अधिकार का दावा किया और कुछ पर उसने मामूली दावा तो किया लेकिन उसके पास इतने बड़े पुरातन दावे को पूरा करने के लिए ताकत नहीं थी। तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान पर उनका हमला और कब्जा 1949 में हुआ, जब चीन में सत्ता पर माओ त्से तुंग का कब्जा हुआ और उन्होंने चीन जनवादी गणतंत्र की स्थापना की, तब तक आंतरिक मंगोलिया और मंचूरिया में चीन अपनी ताकत बना चुका था। आज ने न केवल उन देशों पर भौतिक रूप से कब्जा कर लिया है, बल्कि उसने अधिकृत देशों के लोगों और वहां के इतिहास पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसने सभी देशों से “एक चीन नीति” का समर्थन करने के लिए भी दस्तखत करा लिया है।

fiNys dqN o"kksZa ls frCcr esa vkRenkg dh ygj py jgh gS] Q'k 2009 ls vc rd ,d lkS ls T;knk yksxksa vkRenkg fd;k gS vkSj vdsys uoacj 2013 esa vkRenkg dh 25 ?kVuk,a gqbZ FkhaA bl rjg dh dkjokbZ ds fy, yksxksa dks D;k etcwj gksuk iM+ jgk gS vkSj budk D;k fufgrkFkZ gksxk

वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक के आयोजन के साल समूचे तिब्बती पठार में दूसरी तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति फैल गई थी। इसके बाद चीन सरकार ने वहां इतना ज्यादा सेना, पुलिस और

खुफिया एजेंसियों के जवानों की तैन. ाती कर दी, कि शहर और कस्बे पुलिस छावनी में तब्दील हो गए। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को गोली से भूना जाने लगा और उनके शव को ऐसे दिया जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इस तरह के प्रदर्शनों को गंभीरता से नहीं लिया जाता और मिनटों के भीतर सारे निशान मिटा दिये जाते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, आत्मदाह की कार्रवाई लोगों का ध्यान ज्यादा आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि जलते हुए शरीर को देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं। पुलिस की गोली से मरें या आत्मदाह से दोनों में प्रदर्शनकारी की मौत होती है, लेकिन आत्मदाह विरोध और अवमानना दोनों तरह की कार्रवाई है जिसमें किसी को प्रचार भी खूब मिलता है और उसके विरोध को नोटिस किया जाता है, लोग खुद ही अपना जीवन खत्म कर देते हैं और पीछे केवल राख रह जाती है।

चीनियों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना, आत्मदाह करने वाले तिब्बती एक तरह से अपने शरीर और जीवन को ही उनके हवाले कर देते हैं, लेकिन यह साफतौर से प्रतिरोध की कार्रवाई भी होती है। इसका हर जीवित तिब्बती के दिमाग पर असर यह होता है कि संघर्ष से तत्काल कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा, इससे उनमें बलिदान की भावना बलवती हो रही है और वे कम से कम अगली दो पीढ़ियों तक संघर्ष जारी रख सकते हैं।

सभी आत्मदाह करने वाले तिब्बती या तो लिखित रूप में या ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग में अपने संदेश छोड़कर जाते हैं और वे आत्मदाह करने के दौरान जिस तरह के नारे लगाते हैं उनसे यह साफ है कि वे चीन के बर्बर कब्जे में नहीं रहना चाहते और इसलिए वे परमपावन दलाई लामा की वापसी और तिब्बत की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को तिब्बत पर चीन के बर्बर कब्जे के बावजूद चीन के साथ व्यापार में फायदा हो रहा है, इसलिए यह आत्मदाह चीन के समान ही बाकी दुनिया के लोगों के लिए भी उतना ही संदेश देता है।

o"k 2002 e vki ecb d vkcjk; gkVy dh jfyx ij p< x, tgk phuh i/kkue=h >jkxth Bgj g, Fk vkj frCcr dk vktkn djk] phu ckgj tkvk dk cuj ygjku yxA blh rjg tc 2005 e tc phuh i/kkue=h ou ft;kckvk cxy# dh ;k=k ij vk, Fk rk vki 200 QV Åp Vkoj dh ckyduh e p<dj Ýh frCcr d cuj ygjku yxA bl rjg dk dk;l fdruk dfBu Fkk\ D;k vki Hkfo"; e Hkh bl rjg dh dkjokb djx

जब कोई बर्बर व्यक्ति सज्जन बनने का बहाना करता है तो वह बुजदिल तरीके से अपनी बर्बरता को और उजागर ही कर देता है। उक्त दोनों मामलों में मीडिया ने चीन से ज्यादा तिब्बत के बारे में चर्चा की और लोगों को तिब्बत पर चीनी कब्जे की जानकारी हुई। दबंग चीन इससे इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ कि अगली बार जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए तो चीन के अनुरोध मुझे पकड़कर कुत्ते की तरह धर्मशाला के छोटे से हिल स्टेशन पर कैद रखा गया और 20 दिन तक 24 भारतीय पुलिसकर्मी मुझ पर नजर रखे रहे। मीडिया ने इस खबर को खूब प्रचारित किया और एक छोटे से दुबले–पतले तिब्बती से चीन के इस डर का खूब मजाक बनाया गया।

vki ÝM l vkQ frCcr d egklfpo gA vkidk lxBu D;k dj jgk g vkj ;g D;k gkfly djuk pkgrk g

फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत भारतीयों के बीच तिब्बत के लिए अभियान चलाने वाले भारतीय समर्थकों का एक व्यापक नेटवर्क है। इसके स्वयंसेवक भारतीयों के बीच विचार–विमर्श, फिल्मों का प्रदर्शन, चर्चा और तिब्बत के मसले को दर्शाने वाली प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। भारतीयों को इस बारे में भी जागरूक किया जाता है कि तिब्बत की स्वाधीनता भारत के हित में है और तिब्बत पर चीनी कब्जे की वजह से ही हिमालय की 4075 किलोमीटर लंबी सीमा पर बुनियादी रूप से खतरा पैदा हुआ है। मैं भी इस आंदोलन का एक स्वयंसेवक हूं।

frCcr d fy, vkidk vxy o"kk e D;k gku dh lHkkouk fn[k jgh g

चीन के साथ बढ़ते वैश्विक व्यापार की वजह से तिब्बत के दमन का फायदा सबको मिल रहा है। तिब्बत से जो सोना, तांबा और लीथियम निकाला जाता है, उसकी वजह से ही 'मेड इन चाइना' उत्पाद सस्ते होते हैं। पूर्वी तुर्किस्तान और दक्षिणी मंगोलिया से निकले तेल एवं गैस की मदद से ही चीन में दुनिया भर की कंपनियों के उद्योग चलते हैं। इसलिए हमें तो अभी कुछ समय तक धैर्य रखना होगा। लेकिन पश्चिमी दुनिया ने भी यह समझ लिया है कि मुनाफा देने वाले सस्ते मेड इन चाइना उत्पादों का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वे अपने कारखाने भारत, बांग्लादेश और बर्मा ले जाने की योजना बना रहे हैं। इससे हमें उम्मीद जगी है, हम काफी निडर और साहसी लोग हैं, हम तब तक प्रतिरोध करते रहेंगे, जब तक हमारा अस्तित्व है।

vc dN gYdh&QYdh ckr dj] ,y if=dk }kjk djkb xb okfVx e Hkkjr d 50 lcl T;knk LVkbfy'k ykxk e pu tku ij vkidk dlk yx jgk g

यह मजाक जैसा है। ◆

द सीआईए सर्कस: तिब्बत्स फॉरगेटन आर्मी

¼vkj lsuxqIrk] vkmVyqd½

सीआईए ने किस तरह से एक युद्ध को प्रायोजित किया और तिब्बतियों को धोखा दिया, जिसके बारे में दुनिया नहीं जान पाई

इसका कोड नाम 'एसटी सर्कस' था। लेकिन सीआईए ने जिस तरह से तिब्बती आंदोलनकारियों को आर्थिक मदद दी, प्रशिक्षित किया, हथियार दिए और आखिर में धोखा दिया, वह कोई मजाक की बात नहीं है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने इस व्यापक छवि को हिलाकर रख दिया है कि 1951 में मामूली प्रतिरोध के बाद अहिंसक तिब्बतियों ने चीनियों को ल्हासा में आसानी से घुस जाने दिया। एक युद्ध जो तेनजिन सोनम और उनकी पत्नी रितु सरीन के द्वारा बीबीसी के लिए बनाई गई दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री द शैडो सर्कसः द सीआईए इन तिब्बत में फिर से जीवंत हो गया है।

यह डॉक्यूमेंट्री प्यार की मेहनत है और ऐसा इसमें दिखता भी है। बिना किसी अंध देशभक्ति दिखाए इस बेहतरीन शॉट वाले डॉक्यूमेंट्री–जिसका निर्माण दस साल पहले शुरू किया गया था–में काफी जीवंत तरीके से यह दिखाया गया है कि किस तरह से कुछ हजार तिब्बतियों ने चीन की विशाल जनमुक्ति सेना से लोहा लिया। मामूली सैन्य बल और संख्या वाले इन तिब्बतियों ने दशकों तक दुनिया की छत पर एक खूनी गुरिल्ला लड़ाई लड़ी। और उस समय उनका सहयोगी थाः सीआईए।

तेनजिन के पिता ल्हामो सेरिंग इस प्रतिरोध के एक वरिष्ठ नेता थे और तिब्बत अभियान के लिए सीआईए के मुख्य समन्वयक। वर्ष 1958 में उन्हें वर्जीनिया और कोलोराडो के चट्टानों वाले पहाड़ों पर सीआईए के शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने इस पूरे आंदोलन का दस्तावेज तैयार किया और कई अन्य विषयों पर भी लेखन किया। इस साल 9 जनवरी को उनकी मौत हो गई तिब्बत को आज़ाद देखने का सपना पूरा हुए बिना, द शैडो सर्कस उनके लिए एक श्रद्धांजलि की तरह है।

चीन ने 1949 के अंत में तिब्बत पर चढ़ाई की और इसके दो साल बाद उन्होंने बहादुर लेकिन छोटी तिब्बती सेना को परास्त करते हुए ल्हासा में प्रवेश कर लिया। उस समय सिर्फ 17 साल के दलाई लामा को चीन के साथ एक असहज समझौता करना पड़ा। लेकिन जब 1956 में पूर्वी तिब्बत के मठों को उजाड़ दिया गया तब स्थानीय खम्पा आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया और एक भूमिगत संगठन बनाकर मदद के लिए कई तरफ गुहार लगाई। भारत में निर्वासन में रह रहे दलाई लामा के बड़े भाई ग्यालो थोनडुप ने अमेरिकियों से संपर्क करने का वादा किया। उस समय कम्युनिस्टों से बेहद डरे अमेरिकियों ने खुशी से मदद करना स्वीकार कर लिया। खम्पाओं में से छह लोगों के एक समूह का चयन कर उन्हें भारत भेजा गया। उन्हें गुपचुप तरीके से प्रशांत महासागर के द्वीप साइपन ले जाया गया जहां उन्हें गुरिल्ला युद्ध और गुप्त रेडियो संचार का प्रशिक्षण दिया गया।

इसके पांच महीने बाद, नई दिल्ली में रहने वाले अथार नोर्बू और उनके एक साथी तिब्बत में पैराशूट से भेजे जाने वाले पहले लोगों में से थे। तब तक प्रतिरोध ल्हासा से बाहर दक्षिणी तिब्बत तक पहुंच गया था। चीनियों के विरुद्ध उनकी सफलता को देखते हुए सीआईए को इस प्रतिरोध को हथियार आपूर्ति करने को प्रेरित होना पड़ा। इसके बाद इस एजेंसी ने रॉकी पहाड़ों पर एक अति गोपनीय प्रशिक्षण शिविर लगाए, जहां का वातावरण बिल्कुल तिब्बत की तरह तैयार किया गया। अगले पांच साल में कैम्प हेल में 259 तिब्बतियों को प्रशिक्षण दिया गया।

तेनजिन सुलत्रिम ने कहा, "जब हम अमेरिका गए तो हमें काफी उम्मीदें थीं। हमें ऐसा लगता था कि वे तो हमें लौटने पर परमाणु बम भी दे सकते हैं।" एक और बुजुर्ग तिब्बती ने कहा, "प्रशिक्षण के दौरान हमने यह सीखा कि हमारा लक्ष्य अपनी आज़ादी हासिल करना है।" लेकिन अमेरिकी कुछ और सोच रहे थे। सीआईए के एजेंट सैम हैलपर्न ने कहा, "पूरी सोच यह थी कि चीनियों को फंसाए रखा जाए, उन्हें नाराज और परेशान किया जाए। कोई भी तिब्बत को लेकर युद्ध नहीं करना चाहता था...यह थोड़ा सा उत्पात मचाने वाला ही अभियान था। बुनियादी रूप से इससे ज्यादा कुछ नहीं।"

मार्च 1959 में सीआईए ने तिब्बत में दूसरी बार हथियार गिराए जहां प्रतिरोध बड़े इलाकों में फैल गया था। उधर ल्हासा में स्थानीय चीनी सेना के शिविर में दलाई लामा को एक नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन निमंत्रण पत्र में लिखा था कि उन्हें अपने अंगरक्षकों के बिना आना है। ल्हासा के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, दलाई लामा को समझ में आ गया कि अब ल्हासा छोड़कर जाने का समय आ गया है।

इसके कुछ दिनों बाद एक सैनिक के वेश में दलाई लामा महल से निकल गए और दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। सीआईए से प्रशिक्षित रेडियो टीम उनसे रास्ते में मिली और उन्होंने अमेरिकियों से कहा कि वे दलाई लामा को भारत में शरण दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू से अनुरोध करें। स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ नेहरू ने तत्काल ही इसे मंजूर कर लिया। इसके बाद 31 मार्च, 1959 को पहाड़ों की दुर्गम यात्रा कर दलाई लामा और उनका का. फिला भारत में प्रवेश किया। उनके साथ तिब्बत से भारी संख्या में शरणार्थी भारत आए जिससे दक्षिणी तिब्बत में प्रतिरोध करने वाले थोड़े ही लोग बचे रहे। ले. किन इससे अविचलित सीआईए ने कैम्प हेल में प्रशिक्षण लेने वाले तिब्बतियों के चार ग्रुप को 1959 से 1960 के बीच पैराशूट से तिब्बत में उतारा ताकि वे बचे हुए प्रतिरोध संगठनों से संपर्क कर सकें। लेकिन इस समूह के लगभग सभी सदस्यों की हत्या कर दी गई।

सीआईए ने तिब्बत से सटे नेपाल के सीमावर्ती इलाके मुस्तांग में नये सिरे से अभियान शुरू किया। करीब दो हजार तिब्बतियों ने यहां जुटकर अपनी आज़ादी की लड़ाई जारी रखी। इसके एक साल बाद सीआईए ने मुस्तांग में पहली बार हथियार पहुंचाए। आधुनिक सेना की तरह संगठित इन गुरिल्ला योद्धाओं का नेतृत्व पूर्व भिक्षु बापा येशी कर रहे थे। येशी ने बताया, "जैसे ही हमें मदद मिली, अमेरिकियों ने हमें बच्चों की तरह डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तत्काल तिब्बत के भीतर जाना होगा। उस समय मैंने सोचा कि इससे अच्छा उन्होंने हमें हथियार नहीं दिए होते।" मुस्तांग के गुरिल्ला योद्धाओं ने कई बार नेपाल की सीमा से तिब्बत में छापेमारी की। सीआईए ने मुस्तांग के सैनिकों को दो बार और हथियार पहुंचाए, अंतिम बार मई 1965 में। वर्ष 1969 की शुरुआत में सीआईए ने अचानक सभी तरह की सहायता बंद कर दी। सीआईए ने बताया कि अमेरिका के साथ राजनयिक रिश्ते रखने के लिए चीनियों की मुख्य शर्तों में से एक यह भी था कि तिब्बतियों से पूरा संपर्क और उनको दी जाने वाली सहायता बंद की जाए। सीआईए के पूर्व अधिकारी रोजर मैकार्थी ने बताया, "इसके बावजूद हमने चालाकी दिखाई, हम जिस तरह से चाहते थे, उसी तरह अपने हाथ वापस खीचें।"

जिंदा प्रतिरोध लड़ाकों में से एक थिनली पालजोर उन हजारों तिब्बतियों में से थे जिन्हें सीआईए के पाला बदलने से काफी झटका लगा था। उन्होंने कहा, "हम ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, हमें लगा कि अब सीआईए के लिए हमारी जरूरत खत्म हो गई है। वे सिर्फ अपने व्यक्तिगत अल्पकालिक फायदे के बारे में सोच रहे थे, तिब्बती जनता के दीर्घकालिक हितों के बारे में नहीं। वर्ष 1974 में चीनियों द्वारा सख्ती दिखाए जाने के बाद नेपाल सरकार ने भी मुस्तांग में अपनी सेना भेजकर तिब्बती गुरिल्लाओं से समर्पण करने को कहा। खून–खराबे के डर से दलाई लामा ने प्रतिरोध करने वाले लड़ाकों को अपने टेप वाला संदेश भेजकर समर्पण करने का अनुरोध किया। गुरिल्ला सैनिकों ने अनिच्छा से आत्मसमर्पण किया। कुछ ने तो इसके बाद ही आत्महत्या कर ली।

आज भी मुस्तांग प्रतिरोध में बचे लड़ाके नेपाल में दो शरणार्थी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं, जहां वे ऊन कताई और कालीन बुनाई कर अपना गुजारा करते हैं। तेनजिंग कहते हैं, "यह फिल्म उन युवा तिब्बतियों के लिए जो इस प्रतिरोध से अनभिज्ञ हैं और उन अमेरिकियों के लिए भी जो यह नहीं जानते कि उनकी अपनी सरकार ने इस प्रतिरोध को धोखा दिया है।" रितु ने कहा, "यह कहानी बताई जानी जरूरी थी, लेकिन इसके लिए फंड जुटा पाना लगभग असंभव था।"

यह दंपती वर्ष 1983 से ही फिल्मों का निर्माण कर रहा है और उन्होंने पुनर्जन्म से लेकर, कैलिफोर्निया के प्रवासी सिख समुदाय और तेनजिंग की पहली तिब्बती यात्रा तक पर फिल्में बनाई हैं। वे तिब्बत पर एक पूरी फीचर फिल्म भी बनाने जा रहे हैं, लेकिन शैडो सर्कस को भी तमाम आश्चर्यजनक खुलासों के लिए याद रखा जाएगा।

सबसे हृदयस्पर्शी यादें तेनजिंग के पिता की हैं: "हमने अपने तरफ से तो अमेरिकियों की मदद का इस्तेमाल करने में सक्षम रहे। हम खाली हाथ तो चीनियों से नहीं लड़ सकते थे। मैं हमारे सशस्त्र संघर्ष को सिर्फ इस तरह से नहीं देखता कि इससे इतिहास में कुछ बिंदु तक मदद मिली, ऐसा संघर्ष जो खत्म हो गया। इसे हमें आज़ादी के लगातार चल रहे संघर्ष के एक अध्याय की तरह ही देखना चाहिए, ऐसा संघर्ष जिसका जिसकी अब भी कुछ सार्थकता है।" ◆

सेवन ईयर्स इन तिब्बत

हेनरिक हैरर (अनुवाद रॉबर्ट ग्रेव्स)
समीक्षक जॉन

यह पुस्तक हैरर के तिब्बत और अनछुए शहर ल्हासा में बिताए गए दिनों की दिलचस्प यादें हैं और वह भी इस एकांतप्रिय देश में आज़ादी के अंतिम वर्षों की। हैरर एक आस्ट्रियाई पर्वतारोही थे जो हिमालय की यात्रा से लौट रहे थे, जब द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया। वह और उनके साथी जल्दी ही उत्तर भारत के एक ब्रिटिश युद्धबंदी शिविर में पहुंचा दिए गए। हालात सामान्य होने पर हैरर ने वहां से भागने का निश्चय किया और इसके लिए सीधे उत्तर में तिब्बत की ओर जाने की सोची और इसके बाद उनकी योजना चीन या बर्मा होते हुए जापान पहुंचने की थी। कुछ शुरुआती दिक्कतों के बाद वह और उनके साथी भागने में कामयाब रहे और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए तिब्बत पहुंच गए। उस समय तिब्बत एक रहस्यमय देश था तो होते जिससे बाकी दुनिया के लोग बहुत मतलब नहीं रखते थे और तिब्बत भी वह विदेशियों का बहुत स्वागत नहीं करता था। लेकिन इन दोनों आस्ट्रियाई नागरिकों को उम्मीद थी कि युद्ध में तिब्बत के निष्पक्ष रहने का उन्हें फायदा मिलेगा और इसी वजह से वे पूर्व की ओर बढ़ने लगे। इस तरह तिब्बती पहाड़ों से होते हुए अछूते शहर ल्हासा की सैकड़ों मील लंबी दो साल तक चलने वाली दुर्गम चढ़ाई शुरू हुई। उनके पास देश में प्रवेश करने का कोई परमिट या आधिकारिक यात्रा दस्तावेज तो था नहीं, इसलिए उनको हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि उन्हें कहीं इस देश के लोग वापस न भेज दें और वह पूरी तर अपने झूठ–फरेब और अजनबी लोगों की दयालुता पर निर्भर थे। कई तरह के साहसिक मौकों से गुजरने के बाद आखिर वे ल्हासा पहुंच ही गए जो एक ठंड से जकड़ते, मैले–कुचैले, भूखे और कंगाल स्थिति में।

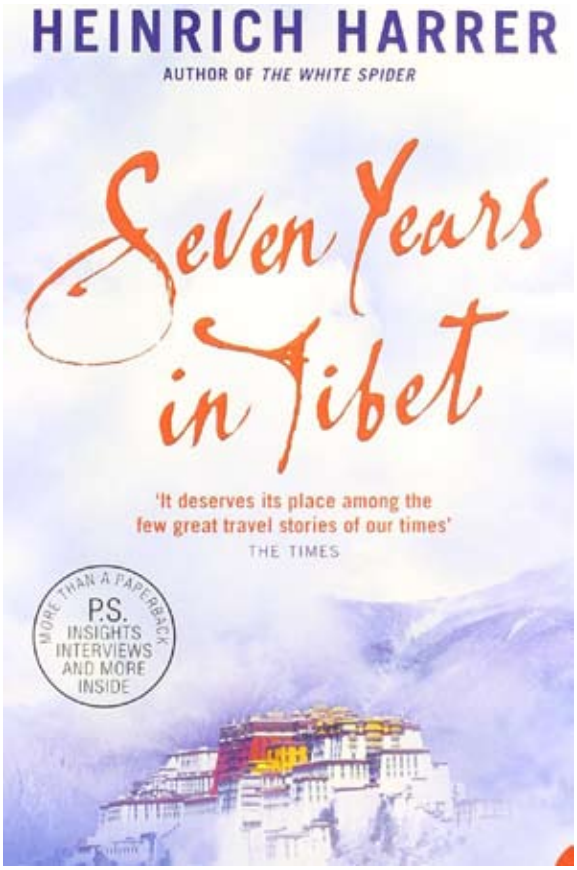

अपनी इस दशा के बावजूद वे फिर आखिरकार तिब्बतियों की स्वाभाविक दयालुता और आतिथ्य पर निर्भर थे। हमेशा भगा दिये जाने के डर के बावजूद धीरे–धीरे उन्होंने अपने मित्रों और संपर्कों का एक नेटवर्क तैयार कर लिया और असल में अजनबी पश्चिमी लोगों के प्रति स्थानीय लोगों की जिज्ञासा से भी उन्हें लाभ मिला। हैरर और उनके साथी ऑफशनेटर ने इस परिस्थिति में अपने को ढालने का पूरा प्रयास किया, वे स्थानीय रीति–रिवाजों का पालन करते रहे और हमेशा मददगार बनने की कोशिश की। उन्हें इस हद तक सफलता मिल गई कि हैरर जल्दी ही उस देश के राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता युवा दलाई लामा के एक तरह के शिक्षक और दोस्त बन गए। वे पांच साल तक उस देश में रहे और तब ही छोड़ा जब वहां चीनी सेना ने आक्रमण और कब्जा कर लिया जिसके बाद आखिरकार दलाई लामा को भी तिब्बत छोड़ना पड़ा। यह किताब इस सरल एकांत देश के बारे में दिलचस्प आंतरिक कहानियों, उसके बौद्ध प्रभुत्व वाली संस्कृति और उसके दोस्ताना रवैये वाले लोगों की गाथाओं से भरी पड़ी है। कई तरीकों से तिब्बत सैकड़ों साल पीछे रह गया देश लगता था–वह लगभग सभी तरह की टेक्नोलॉजी से दूर था, प्रार्थना और अंधविश्वास की ताकत पर भरोसा करता था और शेष दुनिया से लगभग पूरी तरह कटा हुआ था। उसकी बुनियाद एक मजबूत जागीरदारी जैसी थी, लोग भगवान जैसी ताकत वाले युवा नेता पर भरोसा करते थे और वह बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह से कटा हुआ था। यह देश और वहां के लोग इन दो आस्ट्रियाई नागरिकों के प्रति आकर्षित थे और इसलिए वे उनकी कई तरह से मदद करने को तैयार थे।

दुखद यह है कि इस सरल समाज को कुचल दिया गया और उनको अपनी सभी पहचान मिटाने को मजबूर किया गया। विडंबना यह है कि दुनिया से अलग–थलग रहना पसंद करने वाले तिब्बतियों की यही इच्छा उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुई। जब उन्हें अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश से खतरे का सामना करना पड़ा तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। यह पुस्तक न केवल एक रोचक कहानी है, बल्कि इसमें उस संस्कृति के बारे में एक कीमती ऐतिहासिक दस्तावेज मिलता है जिसका अब अस्तित्व नहीं है और आश्चर्यजनक तरीके से जिसका कुछ बाहरी लोगों ने अनुभव किया था। ◆